

कोयला मंत्रालय की चार वर्ष की उपलब्धियाँ एवं अभनिव कदम

संदर्भ

हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा चार वर्षों की उपलब्धियों को जारी किया गया है। इन 4 वर्षों (2014-18) में कोयला उत्पादन में 105 मिलियन टन की वृद्धि हुई, जैसा हासिल करने में 2013-14 से पहले लगभग सात वर्ष लगे थे।

महत्त्वपूर्ण बढि

- पछिले चार वर्षों के दौरान वशिष्ट कोयला उपभोग (प्रति यूनिट बजिली के लिये आवश्यक कोयले की मात्रा) में 8 प्रतिशत की कमी आई है जो 'सरकार की साफ नीयत, सही वकिस' के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।
- देश के कोयला क्षेत्र में सुधार ने ऊर्जा क्षमता, दक्षता एवं सुरक्षा बढोतरी में योगदान दिया है।
- अब तक का सर्वाधिक महत्वाकांक्षी कोयला क्षेत्र सुधार, वाणज्यिक कोयला खनन उच्चतर नविश एवं बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन में सहायक होगा।
- 'शक्ति' योजना के तहत-16 ईंधन आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- केंद्र सरकार ने कोयला एवं रेल मंत्रालय के बेहतर समन्वयन के ज़रिये बेहतर माल ढुलाई पर भी फोकस किया है।
- कोल इंडिया का कोयला लदान 2014-15 के 195 रिक प्रतिदिन से बढ कर 2017-18 में 230 रिक प्रतिदिन हो गया है।
- 14 महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये कोयला निकालने हेतु समयबद्ध कार्य नषिपादन की समय-सीमा नरिधारित की गई है।
- कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का कोयला उत्पादन 2013-14 के 462 मिलियन टन से बढ कर 2017-18 में 567 मिलियन टन तक पहुँच गया है।
- उत्खनन के क्षेत्र 2013-14 के 6.9 लाख मीटर की तुलना में लगभग दोगुनी बढकर 2017-18 में 13.7 लाख मीटर तक पहुँच गई।
- बढे हुए कोयला उत्पादन से 'सभी के लिये 24 घंटे कफायती बजिली' के वज़िन को साकार करने में मदद मिलेगी, जो 2022 तक नवीन भारत वज़िन का एक हसिसा है।

	अखलि भारतीय कोयला उत्पादन में वृद्धि (मलियन टन में)	सीआईएल कोयला उत्पादन में वृद्धि (मलियन टन में)	अखलि भारतीय कोयला डसिपैच में वृद्धि (मलियन टन में)	सीआईएल कोयला डसिपैच में वृद्धि (मलियन टन में)
2010-11से 2013-14	33	31	48.6	46.62
2014-15से 2017-18	67	73	87.76	91.44
4 वर्षों की अवधि में वकिस की प्रतिशत वृद्धि	103%	135%	80.6%	96.14%

मंत्रालय ने उत्कृष्ट कोयला गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये किस प्रकार कार्य किया है?

- तीसरे पक्ष की नमूना प्रक्रिया लागू की गई है।
- कोयला गुणवत्ता निगरानी प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं पक्षता सुनिश्चित करने के लिये उत्तम एप लॉन्च किया गया है।
- कोयला नयित्क संगठन (CCO) द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड एवं सगिरैनी कोलयिरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) के सभी खदानों का पुनर्श्रेणीकरण किया गया है।
- फोकस नमिन लागत एवं उच्च गुणवत्ता के ज़रिये बजिली की लागत पर रहा है और पछिले चार वर्षों के दौरान वशिष्ट कोल उपभोग (प्रति यूनिट बजिली के लिये आवश्यक कोयले की मात्रा) में 8 प्रतिशत की कमी आई है।

कोयला खदानों की पारदर्शी नीलामी एवं आवंटन

- 89 कोयला खदानों की पारदर्शी तरीके से नीलामी की गई है और उन्हें कोयला धारित राज्यों को 100 प्रतिशत राजस्व के साथ आवंटित किया गया है जिससे खासकर, सामाजिक रूप से पछिड़े एवं आकांक्षी जिलों के लिये आर्थिक वकिस सुनिश्चित करने में राज्यों को सहायता मिलेगी।
- 45.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष की पारदर्शी तरीके से गैर-वनिनियमित क्षेत्र को नीलामी की गई है।
- कोयला लकैज की नीलामी एवं आवंटन के लिये भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला को उपयोग में लाने एवं आवंटन करने की योजना (शक्ति) से

कफ़ायती बजिली मलैंगी एवं कोयला के आवंटन में पारदर्शता आएगी ।

अन्य महत्त्वपूर्ण कदम

- बजिली क्षेत्र में कोयला लकैज को युक्तसंगत बनाने के परणामस्वरूप 3,359 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत क्षमता के साथ 55.66 मिलियन टन की कुल कोयला आवाजाही तरकसंगत रूप में सामने आई है ।
- इसके अतरिक्त, कोयले की पर्याप्त आपूर्त सुनिश्चित करने के लयि, चरि प्रतीक्षति टोरी-शविपुर रेल लाइन (44 कर्मी) का एक हसिसा और टोरी-बालूमठ रेल खंड को 9 मार्च, 2018 को आरंभ कर दयिा गया ।
- ओडशिया में झारसुगुडा-बारापल्ली (53 कर्मी) रेल लाइन का कार्य भी पूरा कयिा जा चुका है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/coal-ministry>

